



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1835]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2008/पौष 10, 1930

No. 1835]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2008/PAUSA 10, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2008

का.आ. 3011(अ).—केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्षों के लिए महाराष्ट्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के नाम से (जिसे इसके बाद प्राधिकरण कहा जाएगा) एक प्राधिकरण का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :

1. प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार —अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव/सचिव राजस्व विभाग, महाराष्ट्र सरकार —सदस्य
3. प्रधान सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार —सदस्य
4. प्रधान सचिव (मातृस्यिकी), कृषि, डेयरी विकास और मातृस्यिकी विभाग, महाराष्ट्र सरकार —सदस्य
5. प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, महाराष्ट्र सरकार —सदस्य
6. नगर आयुक्त, ग्रेटर मुम्बई नगर निगम, मुम्बई —सदस्य

7. प्रेजीडेंट, वामराई प्रतिष्ठान, पुणे —सदस्य
8. डॉ. एस. बी. चापेकर (पूर्व डीन, सलीम अली पारिस्थिति विज्ञान स्कूल, पुढुचेरी), मुम्बई —सदस्य
9. डॉ. एस. के. गुप्ता, सीईएसई विभागाध्यक्ष, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई —सदस्य
10. डॉ. (श्रीमती) लीला भोंसले, वास्तुविभाग, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर —सदस्य
11. निदेशक केन्द्रीय मातृस्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई —सदस्य
12. उप-सचिव या उप-सचिव के समकक्ष रैंक का अधिकारी, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार सचिव

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा महाराष्ट्र राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) महाराष्ट्र राज्य सरकार से तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों तथा तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या संशोधन करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना और इस संबंध में राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को सिफारिशें देना;

(ii) (क) उक्त अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, यहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध

प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए निदेश से असंगत न हों ;  
(ख) उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनरावलोकन करना, और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देशित करना :

बशर्ते कि पैरा II के उप-पैरा (ii) (क) और (ii)(ख) के अंतर्गत आने वाले मामलों को अपनी ओर से अथवा किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधिक निकाय अथवा किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर शामिल किया गया है ।

(iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें दर्ज करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

- III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे महाराष्ट्र राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।
- IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।
- V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेगा।
- VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।
- VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके संशोधनों को, जांच और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।
- VIII. प्राधिकरण, उन सभी विशिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा जोकि महाराष्ट्र की अनुमोदित तटीय प्रबंध योजना में निर्धारित की गई हैं।
- IX. प्राधिकरण अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह माह में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

- X. प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा कि बैठकों के दौरान प्राधिकरण के दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहें ।
- XI. प्राधिकरण की पूर्वागामी शक्तियां और क्रियाकलाप केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन होंगे।
- XII. प्राधिकरण का मुख्यालय मुम्बई में स्थित होगा।
- XIII. कोई मामला जो विशिष्टतया प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र और क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, उसे संबंधित सांविधिक प्राधिकरण देखेगा ।

[फा. सं. 12-2/2005-आई ए-III]

डॉ. नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

### ORDER

New Delhi, the 31st December, 2008

**S.O. 3011(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Maharashtra Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely :—

1. Principal Secretary/ Secretary, — Chairperson  
Environment Department,  
Government of Maharashtra.
2. Principal Secretary/Secretary, —Member  
Revenue Department,  
Government of Maharashtra.
3. Principal Secretary/Secretary, —Member  
Urban Development Department,  
Government of Maharashtra.
4. Principal Secretary (Fisheries), —Member  
Agriculture, Dairy Development  
and Fisheries Department,  
Government of Maharashtra.
5. Principal Secretary/Secretary, —Member  
Industries Department,  
Government of Maharashtra.
6. Municipal Commissioner, —Member  
Municipal Corporation of Greater  
Mumbai, Mumbai.
7. President, Vamrai Pratishthan, Pune—Member
8. Dr. S.B. Chaphekar (Former Dean, —Member  
Salim Ali School of Ecology,  
Puducherry), Mumbai.
9. Dr. S.K. Gupta, Head of Department —Member  
of CESE, Indian Institute of  
Technology, Mumbai

10. Dr. (Mrs.) Leela Bhosle, —Member  
Department of Botony,  
Shivaji University, Kolhapur

11. Director, Central Institute of Fishery —Member  
Education, Mumbai.

12. Deputy Secretary or Officer not below —Member  
the rank of Deputy Secretary, Secretary  
Environment Department, Government  
of Maharashtra.

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the State of Maharashtra, namely :—

(i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Maharashtra State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefore;

(ii) (a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under Section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government.

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary, referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority :

Provided that the cases under sub-paragraphs (ii) (a) and (ii) (b) of paragraph II may be taken up *suo motu* or on the basis of complaint made by an individual or an representative body or an organization;

(iii) filling complaints, under Section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the

directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order;

(iv) to take action under Section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of the Order.

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the State Government of Maharashtra the National Central Zone Management Authority or the Central Government.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas.

VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modification thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Maharashtra.

IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

X. The Authority shall ensure that at least two-third members of the Authority are present during the meetings.

XI. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XII. The Authority shall have its headquarters at Mumbai.

XIII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 12-2/2005-IA-III]

Dr. NALINI BHAT, Scientist 'G'